विचार बिन्दु

पछतावा ह्रदय की वेदना है और निर्मल जीवन का उदय। –शेक्सपियर

समग्र विकास के लिए प्रारम्भिक शिक्षा नितांत आवश्यक है।

इस बार के बजट भाषण में राज्य के वित्त मंत्री ने शिक्षा का सतही जिक्र किया है। पर्यटन के चकाचौंध करने वाले आयोजनों की उसमें बात है मगर जब शिक्षा की बात आई तब वह असली बात छूट गई कि शिक्षा के सरकारी संस्थानों में पढ़ाई की व्यवस्था कैसे सुधरेगी। बजट भाषण में शिक्षा के प्रति सरकार का रवैया आशा नहीं बांधता। वित्त मंत्री ने युवाओं के रोजगार की भावी सुनहरी तस्वीर बनाने की कोशिश की मगर प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ किये बिना वह किस प्रकार होगा यह सवाल बना रह जाता है। राज्य का अपना चरित्र बदल गया है। पूंजी की प्रभुता एक शक्तिशाली विचारधारा बन चुकी है। अब सरकारों को दिखावे वाले भव्य मनोरंजन के खर्चीले आयोजनों में निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं होती, किन्तु शिक्षा की बेहतर व्यवस्था करने में उन्हें पैसे की बाधा आती है। लगता है किसी को याद ही नहीं है कि विकास की कुंजी सिर्फ एक होती है, और वह है शिक्षा। मानव संसाधन को उपयोगी बनाने के लिए बच्चों और युवाओं को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करके ही उन्हें उत्पादकता वाली आर्थिक गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है और उन्हें जिम्मेवार नागरिक बनाया जा सकता है। देश की 140 करोड़ की आबादी में जो थोड़े अमीर लोग हैं वे अपने अलग महंगे शिक्षा संस्थान बना कर अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा कर तैयार कर लेते हैं और उन्हें बाजार में अपना स्थान बना लेने लायक बना देते हैं, किन्तु आर्थिक रूप से कमजोर बहुसंख्यक आबादी सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था के भरोसे रहती है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की भूमिका विकास के किसी भी अन्य काम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत का संविधान भी अपने नीति निर्देशों में राज्य पर सब बालकों को समान शिक्षा देने की व्यवस्था करने का दायित्व डालता है। दुर्भाग्य से वर्तमान राज व्यवस्था में बैठे प्रतिनिधि भले जी बहुसंख्यक गरीब आबादी के मतों से चुन कर आते हैं, मगर शासन में बैठ कर वे अमीर वर्ग के लिए हो रहते हैं। वित्त मंत्री का अपने बजट भाषण में शिक्षा का जिक्र कर्मकांड बन कर रह जाना इसी दृष्टि से देखा जा सकता है। शिक्षा के प्रति यह रवैया एक बड़े पेशे को गिरा दिए जाने का संकेत भी है। शिक्षा व्यवस्था की तबाही के दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो शिक्षकों के आत्मसम्मान का क्षय होना और उनका अपने पेशे को केवल सरकारी बाबुओं वाला रोज़गार मानने लगना होता हैं। दूसरा यह कि विद्यार्थियों के शिक्षण में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करने की कोई कोशिश न होना, जो शिक्षा का राजनीति की शिकार हो जाने से होता है। नई राजनीतिक धारा को शिक्षक के श्रम की गरिमा गवारा नहीं है। सभी शिक्षण संस्थान नौकरशाही की संस्कृति में डूबे हैं। इस संस्कृति में रोजमर्रा के नियम, आदेश और दंड की व्यवस्था होती है, पर रचनात्मकता नहीं होती है, या फिर वह इतनी कमजोर होती है कि वह किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज़रूरी ऊर्जा और इच्छाशक्ति को जन्म नहीं दे पाती। मुट्ठी भर शिक्षक छात्रों को प्रेरित या संवेदित महसूस करा पाते हैं, शेष का कक्षाओं में पढ़ाना रोज अखबार पढ़ने की आदत जैसा हो गया है। शालाओं तथा विश्वविद्यालयों का प्रशासन स्वयं इतना कमज़ोर और स्थानीय नेताओं की कृपा पर निर्भर हो गया है कि उसे शिक्षण की नीरसता से कोई हर्ज़ नहीं होता। बजट में इस नीरसता को तोड़ने के लिए किसी निवेश का जिक्र नहीं है।

बजट भाषण में शिक्षा को जिस चलताऊ तरीके से लिया गया है जिसमें कुछ नए संस्थान खोल देने या क्रमोन्नत कर देने के रस्मदायगी यही दिखाती है कि शासन में शिक्षा की समस्याओं को सुलझा लेने की इच्छाशक्ति नहीं रही है। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बड़ा शोर है, लेकिन राज्य सरकार ने नीति के अनुरूप क्या कदम उठाये हैं और आगे नीति पालकों की क्या योजनाएं हैं उस पर चुप्पी के क्या निहितार्थ हो सकते हैं। इन सवालों के जवाब मतदाता जरूर जानना चाहते है क्योंकि ये प्रवृत्तियां आज इतनी उजागर हो चुकी हैं कि उनका प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा मनुष्य मे निहित शारीरिक, मानसिक एवं श्रेष्ठतम आत्मिक शक्तियों का अधिकतम विकास है यह समझ पाना आज के प्रचार माध्यमों के जरिए पनपे राजनेताओं के लिए संभव नहीं है। इसीलिए शिक्षा उनकी प्राथमिकताओं में नीचे चली जाती है। वे आर्थिक प्रगति की बातें तो जोरों से करते हैं मगर यह याद नहीं रखते कि ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ एक साथ रहते हैं। शिक्षा को महत्व देना मानव पूंजी के महत्व को पहचानना है। समग्र विकास की रणनीति में मानव संसाधन विकास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मानव संसाधन विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को संतुलित करने में मददगार होती है। बजट में युवाओं के कौशल विकास की बात कही गई है किन्तु प्रारम्भिक शिक्षा की मजबूती के बिना इसका लाभ कैसे होगा बड़ा सवाल है। प्राथमिक शिक्षा बड़ा निवेश मांगती है और स्कूलों में पूरी संख्या में असली शिक्षकों की अपेक्षा करती है। शिक्षा की अनुपूरक अनुदान मांगों पर भी सदन में सिर्फ एक दिन की चर्चा रखी ही गई है वह भी मौजूदा माहौल में एक रस्मअदायगी बनकर रह जाने वाली है। यह नहीं भूल जाना चाहिए कि बजट भाषण में सरकार की दृष्टि प्रकट होती है और वह दृष्टि मौजूद बजट में शिक्षा के प्रति गंभीर नज़र नहीं आती। सरकार को शिक्षा के प्रति गंभीर बनाने के लिए विपक्ष के पास भी कोई रणनीति नहीं है। शिक्षा के प्रति सरकार का यह सरोकार साबित करता है कि शिक्षा में बिखराव स्वाभाविक नहीं है। वह आयोजित नज़र आता है। जब ऐसा बिखराव आता है तब सभ्यता टूटती है, विकृतियां पनपती हैं। इसे हम वृहद भारतीय समाज में होता देख भी रहे हैं। संचार की नई टेक्नॉलाजी के बढ़ते वर्चस्व में शिक्षा के प्रशासन और प्रबंधन की विकृत तरकीबें ईजाद हुईं हैं और अमल में आने लगीं हैं। शिक्षा का भोंडा बाजारीकरण हमारे सामने है। युवा हाथों में डिग्रियां होने पर भी उनके पास काम नहीं है। जयपुर और कोटा कोचिंग के हब बन गये तथा अन्य शहरों में भी कोचिंग का धंधा खूब फल-फूल रहा है। शिक्षा उद्योग और व्यापार हो गया है। उच्च शिक्षा एक सांस्कृतिक निधि होती है और उसकी नींव प्राथमिक शिक्षा की होती है। सार्वजनिक क्षेत्र में दोनों के हाल बेहाल है। मगर शासन में बैठे जन प्रतिनिधियों तथा बजट बनाने वाली सरकारी तंत्र का इससे कोई सरोकार नज़र नहीं आता। जब बजट में शिक्षा का ही स्थान न हो तो उसमें साहित्य को खोजना निरर्थक ही होगा। साहित्य अकादमियों को प्रशासनिक अधिकारियों के पास अतिरिक्त चार्ज के रूप में सौंपा हुआ हो तब राज्य से क्या अपेक्षा हो सकती है। कला साहित्य का सरकार का इसलिए कोई वास्ता नहीं क्योंकि उसे बाजार के सेलेब्रिटीज़ के जरिए पर्यटन में रंगीनियों की धूम चाहिए, भले ही सत्ता में बैठे लोग सादगी वाले उदात्त सनातन मूल्यों का लोक दिखावटी गुण-गान करते रहें। राज्य के बजट की हैसियत वैसे भी कम हो गई है। वह समय गया जब वित्तीय और आर्थिक विश्लेषक ही नहीं आम लोग भी बेताबी से बजट अभिभाषण का इंतजार किया करते थे। अब कोई नहीं करता। जब से जीएसटी की व्यवस्था हुई है तब से अधिकतर कर निर्धारण का काम विधान सभा में बैठे जन-प्रतिनिधियों के पास नहीं रहा है। वह काम अब एक समिति करती है जो राज्य विधानसभा के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यह भी रेखांकित करने वाली बात है कि इस बार कृषि, पर्यटन, पंचायती राज, खनिज, राजस्व, महिला बाल विकास, आबकारी जैसे विभागों की अनुदान मांगों पर इस बार चर्चा नहीं होंगी और वे मुखबन्द के प्रयोग से पारित कर दी जाएगी। कैसी विडंबना है कि एक तरफ बजट भाषण में कृषि का अलग बजट पढ़ा जाता है मगर उसकी अनुदान मांगों पर सदन में चर्चा ही नहीं रखवाई जाती है। जब सदन में निरर्थक मुद्दों पर तू-तू मैं-मैं होती रहे तब वहां किसी गंभीर बहस की क्या उम्मीद रखी जा सकती है। सदन की कार्यवाही मामूली बातों पर बाधित हो जाती है क्योंकि संसदीय परंपराओं की अब कोई परवाह नहीं करता है। शिक्षा का काम है नए ज्ञान की रचना के लिए जरूरी बौद्धिक कौशल और प्रशिक्षण तथा युवा हाथों को हुनर देना। चरणबद्ध रूप से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दिला देने से यह नहीं होने वाला है। फिलहाल उस बीहड़ से निकलने की कोई राह या उम्मीद नज़र नहीं आती क्योंकि औसत राजनेता के पास शिक्षा की पर्याप्त साक्षरता नहीं है। राजनेताओं और शिक्षाविदों के बीच कोई संवाद ही नहीं है। राजनेताओं ने पाठ्यक्रमों में मिथकों के शामिल करने के पैरोकारों को ही शिक्षाविद् मान रखा है। यही हमारे यहां शिक्षा की नीति निर्माण की वास्तविकता है। राजनीतिक व्यवस्था शैक्षिक कार्यक्रम के निर्धारण में एक प्रमुख कारक बनी हुई है। आज के राजनेता लोकतांत्रिक और समानतावादी शिक्षा प्रणाली की जरूरत के बारे में लेशमात्र भी विचार नहीं करते। असमानतावादी और अन्यायपूर्ण समाज से आने वाले राजनेताओं में न तो कठिन निर्णय लेने के लिए साहस है और न बदलाव की इच्छा शक्ति है। वे प्रदेश के लिए 2029 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने को जरूर लालायित है जो शिक्षा और रोजगार के अभाव में समाज में असमानता बढ़ाने वाली ही साबित हो सकती है।

> **राजनेताओं ने पाठ्यक्रमों में मिथकों के शामिल करने के पैरोकारों को ही शिक्षाविद् मान रखा है। यही हमारे यहां शिक्षा की नीति निर्माण की वास्तविकता है। राजनीतिक व्यवस्था शैक्षिक कार्यक्रम के निर्धारण में एक प्रमुख कारक बनी हुई है। आज के राजनेता लोकतांत्रिक और समानतावादी शिक्षा प्रणाली की जरूरत के बारे में लेशमात्र भी विचार नहीं करते। असमानतावादी और अन्यायपूर्ण समाज से आने वाले राजनेताओं में न तो कठिन निर्णय लेने के लिए साहस है और न बदलाव की इच्छा शक्ति है।**

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) ग्रेडिंग: पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता और चुनौतियां

अशोक कुमार

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) प्रमाणन देश भर में उच्च संस्थानों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा के मानक का मूल्यांकन करने का एक उपाय है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी, ने साल 1994 में एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय और संकाय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) (राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद) नामक परिषद से प्रमाणन प्राप्त करना होगा । यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार, अब देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) से मान्यता लेना जरूरी है। अगर किसी भी संस्थान ने इसमें आवेदन कर ग्रेडिंग नहीं कराई है तो उसको किसी भी तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है।

हाल ही में देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) के जरिये होने वाली जांच में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने किया है। जब टीम द्वारा संस्थानों का भ्रमण किया जाता है तो इसी दौरान भ्रष्टाचार की आशंका रहती है. एक-दूसरे के संपर्क में आने से संस्थान की ओर से टीम को उपहार आदि दिए जा सकते हैं। इससे ग्रेडिंग प्रभावित हो सकती है।

सीबीआई ने रिश्वत लेकर शिक्षण संस्थानों को ए ++ रेटिंग देने के मामले में यूपी के गौतमबुद्ध नगर समेत देशभर में 20 ठिकानों पर छापे मारे। इस मामले में की गई छापेमारी में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) की इंस्पेक्शन कमेटी के अध्यक्ष और जेएनयू के एक प्रोफेसर समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले साल 2023 के मार्च में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) के चेयरपर्सन भूषण पटवर्धन ने कई संस्थानों को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) (नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रिडिटेशन काउंसिल) ग्रेडिंग देने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था. रिश्वत मामले में सीबीआई की हालिया गिरफ्तारी के बाद कई को हटाया गया! राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) ने हाल ही में 5,000 मूल्यांकनकर्ताओं में से लगभग 900 को हटा दिया है, जो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) ग्रेड जारी करने से पहले उच्च शिक्षा संस्थानों का दौरा करते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं।

सूत्रों के अनुसार करीब 900 मूल्यांकनकर्ताओं को कई कारणों से हटाया गया है। कुछ सक्रिय नहीं पाए गए या विजिट्स स्वीकार नहीं कर रहे थे, और कुछ ने रिपोर्ट ठीक से तैयार नहीं की थी, जिसका मतलब है कि कुछ मामलों में, उच्च स्कोर देने के कारणों को स्पष्ट रूप से उचित ठहराए बिना कुछ मापदंडों पर शीर्ष स्कोर दिए गए थे, सूत्र ने कहा कि कुछ मूल्यांकनकर्ताओं के पास केवल आंशिक डेटा ही उपलब्ध था। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) ने अप्रैल-मई 2023 में कुछ मूल्यांकनों की समीक्षा शुरू की। हमने ग्रेडिंग के गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं को देखना शुरू किया और यह जांचने का फैसला किया कि क्या कुछ मामलों में दोनों के बीच कोई उल्लेखनीय अंतर है।

रिश्वतखोरी के मामलों ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) ग्रेडिंग प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। समीक्षा से यह सुनिश्चित होगा कि केवल योग्य संस्थानों को ही उच्च ग्रेड मिले। यदि मूल्यांकन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ है, तो संस्थानों को दी गई ग्रेडिंग की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। इससे उन संस्थानों को अनुचित लाभ मिल सकता है जिन्होंने रिश्वत दी, जबकि ईमानदार संस्थानों को नुकसान हो सकता है।

जिन संस्थानों का मूल्यांकन भ्रष्ट मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया गया था, उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन आवश्यक है। समीक्षा से उन संस्थानों की पहचान करने में मदद मिलेगी जिन्हें गलत तरीके से उच्च ग्रेड मिले हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि संस्थानों को उनकी वास्तविक गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग मिले। प्रश्न यह भी है कि क्या एक संस्थान की गुणवत्ता 5 वर्षों तक समान रह सकती है? राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) को मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। संस्थानों की गलत ग्रेडिंग से छात्रों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, और इसके लिए निष्पक्ष मूल्यांकन आवश्यक है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) ग्रेडिंग की समीक्षा के विपक्ष में तर्क दिया जाता है की पिछले 5 वर्षों की सभी ग्रेडिंग की समीक्षा करना एक जटिल और समय लेने वाला काम होगा। इसमें बड़ी संख्या में संस्थानों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) के पास सीमित संसाधन हैं और इतने बड़े पैमाने पर समीक्षा करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी। कुछ संस्थान कानूनी कार्रवाई का सहारा ले सकते हैं, जिससे समीक्षा प्रक्रिया में और देरी हो सकती है।

परिषद ने संस्थानों का मूल्यांकन करने और उच्च शिक्षा संस्थानों को ठोड देने के लिए एक नई नीति अपनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से भौतिक निरीक्षण किया जाएगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) के सूत्रों ने बताया कि विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) की प्रस्तावित ग्रेडिंग नीति – परिपक्वता आधारित ग्रेडेड लेवल का उद्देश्य भौतिक निरीक्षण को समाप्त करना है, क्योंकि उच्च ग्रेड के बदले मूल्यांकनकर्ताओं को रिश्वत देने जैसी 'भ्रष्ट प्रथाओं' का पता ज्यादातर ग्रेडिंग प्रक्रिया के इस चरण में चला है। सरकार और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) को सभी पहलुओं पर विचार करके उचित निर्णय लेना होगा।

–अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
विभागाध्यक्ष राजस्थान
विश्वविद्यालय जयपुर

पशु चिकित्सालय में चिकित्सक एवं सहायक के पद रिक्त, पशुपालक परेशान

समस्याओं को देखते हुए वर्ष 2022 में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण हुआ था

- **हाल ही में सरकार बदलने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पशु चिकित्सक एवं पशुधन सहायक का स्थानांतरण करवा दिया गया था**
- **पशुपालकों को दूर-दराज के अस्पतालों में जाना पड़ रहा है, पशुओं की बीमारियों के समय उचित इलाज न मिलने से किसान भी चिंतित हैं**

पाटन, (निसं)। निकटवर्ती ग्राम पंचायत छाजा की नांगल में लाखों रुपये की लागत से बने पशु चिकित्सालय भवन में बीते तीन महीनों से चिकित्सक एवं पशुधन सहायक नहीं हैं, जिससे पशुपालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पशुपालकों की समस्याओं को देखते हुए वर्ष 2022 में विधायक सुरेश मोदी के प्रयासों से पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण हुआ था। इसके लिए ग्रामवासी दिनेश यादव पुत्र अर्जुनराम ने भूमि दान की थी। चिकित्सालय के शुरू होने से दर्जनों गांवों को लाभ मिला, लेकिन हाल ही में सरकार बदलने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पशु चिकित्सक एवं पशुधन सहायक का स्थानांतरण करवा दिया गया। अब स्थिति यह है कि तीन महीने से दोनों पद रिक्त पड़े हैं, जिससे पशुपालकों को दूर-दराज के अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। पशुओं की बीमारियों के समय उचित इलाज न मिलने से किसान भी चिंतित हैं।

ग्राम पंचायत छाजा की नांगल में लाखों रुपये की लागत से बने पशु चिकित्सालय भवन में बीते तीन महीनों से चिकित्सक एवं पशुधन सहायक नहीं हैं।

इस मुद्दे पर जिला परिषद उम्मीदवार दिनेश यादव ने चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से जल्द चिकित्सक एवं पशुधन सहायक की नियुक्ति करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सालय खुलने से ग्रामीणों को राहत मिली थी, लेकिन अब स्टाफ की कमी के चलते पशुपालक मुश्किलों से जूझ रहे हैं। ग्रामवासियों ने भी सरकार से अनुरोध किया है कि चिकित्सालय को शीघ्र चालू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि पशुपालकों को बेहतर सुविधाएँ मिल सकें।

गांव के आम रास्ते पर अतिक्रमण होने से आमजन सहित छात्र परेशान

आम रास्ते पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण करने से आमजन का निकलना दुभर हो रहा है

- **रास्ता बंद होने से गांव में बच्चों को लेने आने वाली स्कूल बस गांव में नहीं आ रही है**

खेतड़ी, (निसं)। सिंघाना पंचायत समिति के ढाणी हुकमा के ग्रामीणों ने आम रास्ते के अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान आम रास्तों में अतिक्रमण से होने वाली परेशानी से अवगत करवाया गया।

ग्रामीणों की ओर से दिए ज्ञापन में बताया कि हुक्मा की ढाणी से माकड़ों जाने वाले आम रास्ते पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण करने से आमजन का निकलना दुभर हो रहा है। पहले भी अतिक्रमण होने से परेशानी को लेकर ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार द्वारा कार्रवाई कर अतिक्रमण हटवाया गया था, लेकिन अब दोबारा से आम रास्ते में इंटरलॉकिंग ईंट डाल देने से वाहन नहीं निकल पा रहे हैं। इसके अलावा रास्ता बंद होने से गांव में बच्चों को लेने आने वाली स्कूल बस गांव में नहीं आ रही है, जिसके कारण परिजनों की ओर से बच्चों को गांव से बाहर ले जाकर बस में बैठाना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने तहसीलदार से जल्द मौका मुआयना कर अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि जल्द प्रशासन की ओर से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो ग्रामीणों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर राजेंद्र धायल, विकास धायल, अनिल धायल, मनीराम, लालचंद, सुनील कुमार, दीपक, सत्यवीर, सुबेसिंह, हरपाल सिंह, धर्मपाल, रणवीर सिंह, जिले सिंह, प्रदीप कुमार, मोहित सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे।

ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर की अतिक्रमण हटाने की मांग की।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 5 मार्च, 2025

फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठि तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2081, कृत्तिका नक्षत्र रात्रि 1:08 तक, वैधृति योग रात्रि 11:07 तक, तैतिल करण दिन 12:52 तक, चन्द्रमा प्रातः 8:13 से वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-मेष, मंगल-मिथुन, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सम्पूर्ण दिन-रात रहेगा। रवियोग रात्रि 1:08 तक है। आज गोरूपिणी छठ, वैधृति पूण्य है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:45 तक, शुभ 11:12 से 12:38 तक, चर 3:32 से 4:59 तक, लाभ 4:59 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:44, सूर्यास्त 6:30

मेष

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

वृष

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

मिथुन

आर्थिक कारणों से परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। आज घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

कर्क

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

सिंह

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी।

कन्या

नवीन कार्यों के संबंध में उचित सफलता मिलेगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

तुला

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

वृश्चिक

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। आज अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।

मकर

व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक मामलों में परिचितों से उचित सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार से कार्य योजना बनेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को मानसिक तनाव रहेगा। आज परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से सामूहिक वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।